

प्रेषक,

एम0एच0खान  
रायिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक  
उत्तराखण्ड पेयजल निगम  
देहरादून।

पेयजल अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 02 मार्च 2009

विषय: वित्तीय वर्ष 2008-09 में राज्य सैक्टर की नगरीय जलोत्सारण योजना कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद देहरादून की एच0एन0बी0 कालोनी ब्रॉच सीवररेज योजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2875/अप्रैजल-देहरादून/ दिनांक 20.10.08 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर की नगरीय जलोत्सारण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद देहरादून की एच0एन0बी0 कालोनी ब्रॉच सीवररेज योजना अनु लागत रु0 51.29 लाख के प्राक्कलन पर टीएसी वित्त के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि रु0 46.09 लाख में से रु0 23.00 लाख (रु0 तेईस लाख मात्र) राज्य सैक्टर ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत संलग्न बी0एम0-15 के विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत बचतों से पुर्नविनियोग के द्वारा अनुदान मद में एवं रु0 23.09 लाख (रु0 तेईस लाख नौ हजार मात्र) ऋण मद के संगत मद से अर्थात् कुल रु0 46.09 लाख (रु0 छियालिस लाख नौ हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2008-09 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन आपके निर्वहन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउवर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी।

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2009 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

3. कराये जाने वाले कार्यों पर वित्त(वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या 163/XXVII(7)/2007, दिनांक 22.05.08 के अनुसार सेंटेंज प्रभार अनुमन्य होगा।

4. योजना हेतु समस्त अधिप्राप्ति कार्यवाही में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 की अनुपालन सुनिश्चित की जाय।

5. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मानक है। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जायगी।

6. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

र/

7 कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।

8 एक गुप्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9 आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों का तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता के अनुमोदन कराना आवश्यक होगा तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

10— कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

11— कार्य कराने से पूर्व स्थल का भलीभाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू-गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण रिपोर्टों के अनुरूप कार्य किया जाय।

12— आगणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

13— निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला में टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

14— स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही योजना के कार्य पूर्ण किये जायें किसी भी प्रकार से अब पुनरीक्षित प्राक्कलन अनुमन्य नहीं होंगे।

15— ऋण अंश के रूप में स्वीकृत धनराशि की वापसी एवं ब्याज अदायगी निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी:

(1) ऋण मद की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि पूर्व में स्वीकृत ऋणों की अदायगी यदि अभी तक नहीं की गई हो तो ऐसी समस्त धनराशि का समायाजन किये जाने के बाद ही शेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(2) यह ऋण 15(पन्द्रह) समान किश्तों में व ब्याज सहित प्रतिदेय होगा। इस ऋण का प्रतिदान ऋण आहरण की तिथि से एक वर्ष बाद प्रारम्भ होगा। उक्त ऋण पर अन्तिम रूप से 15 (पन्द्रह) प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा, किन्तु निगम द्वारा रागय-संगथ पर ऋण का प्रतिदान/ब्याज का भुगतान करने की दशा में 3-1/2 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, यदि कालातीत न हो अर्थात् अन्तिम प्रभावी ब्याज की दर 11-1/2 (साढ़े ग्यारह) प्रतिशत होगी। ऋण/ब्याज का भुगतान प्रतिदान करने के बाद एक बार भी वित्तिथ हों पर ब्याज की दर में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

(3) ऋणी/संस्था/समिति/कारपोरेशन/स्थानीय निकाय आदि प्रत्येक दशा में ऋण के आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकीय) कार्यालय महालेखाकार (लेखा) प्रथम, उत्तरांचल को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखार्शीषक सूचित करते हुए भेजें।

(4) ऋणी/संस्था/संस्थान जब भी ब्याज जमा करें महालेखाकार कार्यालय को सूचना निम्न प्रारूप पर अवश्य भेजें—

- (1) कोषागार का नाम
- (2) चलान संख्या व दिनांक
- (3) जमा धनराशि।

- (4) लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत जमा किया गया किश्त ब्याज  
(5) शासनादेश संख्या एवं एस0एल0आर0 का संदर्भ किश्त ब्याज  
(6) पिछले जमा का सन्दर्भ।

(5) ऋणी संस्था आहरण के प्रत्येक वर्षगाठ पर अपने लेखों का निदान महालेखाकार के लेखों से अवश्य करें। भविष्य में शासन द्वारा ऋण तभी स्वीकृत किया जा सकेगा जब यह सुनिश्चित हो जाये कि ऋणी संस्था में इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से करा लिया है तथा प्रत्येक अवशेष ऋण की स्थिति यथा समय शासन को अवश्य उपलब्ध करा दें।

16- मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV- 219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य करते समय/कार्य करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

17- भविष्य में सीवरेज कार्यों के प्रस्ताव पूरे नगर के सीवरेज मास्टर प्लान के आधार पर ही प्रस्तुत किये जायें। जिसमें जनसंख्या घनत्व आदि मानकों के आधार पर जोनल प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हो साथ ही चूंकि सीवरेज कार्यों हेतु बड़ी लागत लगती है। अतः यूजर्स चार्जज व्यवहारिक हो इस हेतु नीति निर्धारित की जायेगी। तदर्थ व पैव वर्क आधार पर भविष्य में कोई प्रस्ताव नहीं किया जायेगा एवं सीवरेज कार्य हेतु जेएनएनयूआरएम एवं एडीबी से ही अधिकाधिक वित्त पोषण कराया जाय।

18- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में आय-व्ययक के अनुदान सं0-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2215-जलपूर्ति तथा सफाई-01 जलपूर्ति- आयोजनागत-101- शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम-05 - नगरीय पेयजल-01 - नगरीय पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिए अनुदान-20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता" के नामे तथा ऋण की धनराशि लेखाशीर्षक - "6215-जलपूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज-02 मल-जल तथा सफाई- आयोजनागत - 800- अन्य कर्ज- 04- पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिए ऋण-00-30- निवश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

19- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0- 618/XXVII(2)/2009 दिनांक 02 मार्च 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न- यथोक्त

भवदीय,

(एम0एच0खान)  
सचिव

पू0सं0 272 (1)/उन्तीस(2)/09-2(155 पे0)/2006तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वरिष्ठ कौषाधिकारी, देहरादून।
5. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-2/वित्त(बजट सैल)/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड।
7. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
8. स्टाफ ऑफिसर-मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
9. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)

उप सचिव

# बी0एम0-15 पुनर्विनियोग-2008-09

आयोजनारत

ह अधिकाारी-प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड मेडनल निगम।  
निक विभाग- मेडनल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

रान संख्या-13

प्रविधान तथा लेखाशीर्षक

(रु0 हजार में)

मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के अवशेष अवधि अनुमानित व्यय	अवशेष(स्थलन)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुनर्विनियोग के बाद संरम्भ-5 को कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद संरम्भ-1 में अवशेष धनराशि	अनुमति
2	3	4	5	6	7	8
2215-जलपूर्ति सेवा संचाई			2215-जलपूर्ति सेवा संचाई			(क) इस मद में परिष्कार प्राविधानित न होने के कारण बचत
01-जलपूर्ति-आयोजनागत			01-जलपूर्ति-आयोजनागत			(ख) निर में समुचित धनराशि प्राविधानित न होने के कारण।
102-सामान्य जलपूर्ति कार्यक्रम			101-बाहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
03-ग्रामीण मेडनल राज्य सेक्टर			05-नगरीय मेडनल			
00-			0-नगरीय मेडनल योजना तथा जलसंसारण योजनाओं के लिए अनुदान			
20-सहायक अनुदान/अंशदान व जलसंचयन			20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता			

योग-	600000	131550	168450	300000(क)	2300 (ख)	202300	59770
	600000	131550	168450	300000	2300	202300	59770

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बचत समुचित के परिच्छेद 150, 151, 155, 156 में उल्लिखित सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(नवीन सिंह उद्योगी)  
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त अनुभाग-2  
संख्या 619(क) XXVII-421/2009  
देहरादून दिनांक 02 मार्च 2009

पुनर्विनियोग समूह  
(एमसीओजीसी)  
अपर सचिव वित्त

संवा. नं

महोत्तरीकार,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 619(क) / वनीस / 08-2-(15560) / 2008. तद दिनांक  
प्रविधि निम्नलिखित को सुसंगत एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -  
1-उपसचिवकारी, उत्तराखण्ड। 2 वित्त अनुभाग-2  
3-जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से  
(नवीन सिंह उद्योगी)  
उप सचिव